



THE CORE IAS

UPSC-CSE 2023-2024 के लिए उपयोगी

पिबि
पत्र सूचना कार्यालय
PRESS INFORMATION BUREAU

भारत सरकार

अक्टूबर-2023

www.thecoreias.com



[/thecoreias](https://www.facebook.com/thecoreias)



[/thecoreias](https://www.youtube.com/thecoreias)



[/iascore](https://twitter.com/iascore)



[/thecoreias](https://www.instagram.com/thecoreias)



[/thecoreias](https://www.telegram.com/thecoreias)



विषय सूची



I. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (1-5)

II. रक्षा (6-9)

III. अर्थव्यवस्था (10-12)

IV. पर्यावरण (13-14)

V. इतिहास (15)

VI. भारतीय राजनीति (16-18)

VII.राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय (19-23)

VIII.योजना (24-28)

IX.रिपोर्ट एवं सूचकांक (29)

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

गगनयान



क्या है यह?

- गगनयान परियोजना में 3 दिनों के मिशन के लिए 3 सदस्यों के दल को 400 किमी की कक्षा में लॉन्च करके और भारतीय समुद्री जल में उतरकर उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाकर मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता का प्रदर्शन करने की परिकल्पना की गई है।
- यह परियोजना आंतरिक विशेषज्ञता, भारतीय उद्योग के अनुभव, भारतीय शिक्षा जगत और अनुसंधान संस्थानों की बौद्धिक क्षमताओं के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के पास उपलब्ध अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों पर विचार करके एक इष्टतम रणनीति के माध्यम से पूरी की गई है। गगनयान मिशन के लिए पूर्व आवश्यकताओं में चालक दल को सुरक्षित रूप से अंतरिक्ष में ले जाने के लिए मानव रेटेड लॉन्च वाहन, अंतरिक्ष में चालक दल को पृथ्वी जैसा वातावरण प्रदान करने के लिए जीवन समर्थन प्रणाली, चालक दल के आपातकालीन समय पर चालक दल की पुनर्प्राप्ति और पुनर्वास के लिये प्रावधान और प्रशिक्षण के चालक दल प्रबंधन पहलुओं को विकसित करने सहित कई महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों का विकास शामिल है।
- वास्तविक मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन को अंजाम देने से पहले प्रौद्योगिकी तैयारी के स्तर को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न पूर्ववर्ती मिशनों की योजना बनाई गई है। इन प्रदर्शनकारी मिशनों में इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट (आईएडीटी), पैड एबॉर्ट टेस्ट (पीएटी) और टेस्ट व्हीकल (टीवी) उड़ानें शामिल हैं। मानवयुक्त मिशन से पहले मानवरहित मिशनों में

सभी प्रणालियों की सुरक्षा और विश्वसनीयता सिद्ध की जाएगी।

LVM3 - HLVM3

- LVM3 रॉकेट - इसरो का सिद्ध और विश्वसनीय भारी लिफ्ट लॉन्चर, गगनयान मिशन के लिए लॉन्च वाहन के रूप में पहचाना जाता है। इसमें ठोस चरण, तरल चरण और क्रायोजेनिक चरण शामिल हैं। LVM3 लॉन्च वाहन में सभी प्रणालियों को मानव रेटिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पुनः कॉन्फिगर किया गया है और इन्हें मानव रेटेड LVM3 नाम दिया गया है। एचएलवीएम3 ऑर्बिटल मॉड्यूल को 400 किमी की इच्छित निचली पृथ्वी कक्षा में लॉन्च करने में सक्षम होगा।
- HLVM3 में क्रू एस्कूप सिस्टम (CES) शामिल है जो त्वरित अभिनय, उच्च बर्न दर वाले ठोस मोटर्स के एक सेट द्वारा संचालित होता है जो यह सुनिश्चित करता है कि लॉन्च पैड पर या चढ़ाई चरण के दौरान किसी भी आपात स्थिति के मामले में क्रू मॉड्यूल को चालक दल के साथ सुरक्षित दूरी पर ले जाया जाए।

कक्षीय मॉड्यूल

- ऑर्बिटल मॉड्यूल (ओएम) जो पृथ्वी की परिक्रमा करेगा, उसमें क्रू मॉड्यूल (सीएम) और सर्विस मॉड्यूल (एसएम) शामिल हैं। ओएम मानव सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त अतिरिक्त के साथ अत्याधुनिक एवियोनिक्स सिस्टम से सुसज्जित है।
- सीएम अंतरिक्ष में चालक दल के लिए पृथ्वी जैसे वातावरण वाला रहने योग्य स्थान है। यह दोहरी दीवारों वाला निर्माण है जिसमें थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम (टीपीएस) के साथ दबावयुक्त धात्विक आंतरिक संरचना और बिना दबाव वाली बाहरी संरचना शामिल है। इसमें क्रू इंटरफेस, मानव केंद्रित उत्पाद, जीवन समर्थन प्रणाली, एवियोनिक्स और डिसेलेरेशन सिस्टम शामिल हैं। उतरने से लेकर उतरने तक के दौरान चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इसे पुनः प्रवेश के लिए भी डिजाइन किया गया है।
- कक्षा में रहते हुए सीएम को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए एसएम का उपयोग किया जाएगा। यह एक बिना दबाव वाली संरचना है जिसमें थर्मल सिस्टम, प्रोपल्शन सिस्टम, पावर सिस्टम, एवियोनिक्स सिस्टम और तैनाती तंत्र शामिल हैं।

अन्य:

गगनयान मिशन में मानव सुरक्षा सर्वोपरि है। इसे सुनिश्चित करने के लिए, इंजीनियरिंग सिस्टम और मानव केंद्रित सिस्टम सहित विभिन्न नई तकनीकों को विकसित और साकार किया जा रहा है।

सेरेब्रल पाल्सी**क्या है?**

- सेरेब्रल पाल्सी (सीपी) विकारों का एक समूह है जो किसी व्यक्ति की चलने-फिरने, संतुलन और मुद्रा बनाए रखने की क्षमता को प्रभावित करता है। सीपी बचपन में सबसे आम मोटर विकलांगता है। यह अधिकतर जन्म से पहले विकासशील मस्तिष्क की क्षति के कारण होता है।

लक्षण:

- मांसपेशियों में कमजोरी या अकड़न
- खराब समन्वय
- चलने-फिरने या हिलने-डुलने में कठिनाई होना
- बोलने में कठिनाई
- बौद्धिक विकलांग

कारण:

- मस्तिष्क का असामान्य विकास या विकासशील मस्तिष्क को क्षति जो किसी व्यक्ति की उसकी मांसपेशियों को नियंत्रित करने की क्षमता को प्रभावित करती है।
- गंभीर सेरेब्रल पाल्सी वाले व्यक्ति को चलने में सक्षम होने के लिए विशेष उपकरण का उपयोग करने की आवश्यकता हो सकती है, या वह बिल्कुल भी चलने में सक्षम नहीं हो सकता है और उसे आजीवन देखभाल की आवश्यकता हो सकती है। दूसरी ओर, कम सेरेब्रल पाल्सी वाला व्यक्ति थोड़ा अजीब तरीके से चल सकता है, लेकिन उसे किसी विशेष सहायता की आवश्यकता नहीं हो सकती है।
- सेरेब्रल पाल्सी वाले सभी लोगों को चलने-फिरने और बैठने की मुद्रा में समस्या होती है। कई लोगों में बौद्धिक विकलांगता जैसी संबंधित स्थितियाँ भी होती हैं; दौरे; देखने, सुनने या बोलने में समस्याएँ; रीढ़ में परिवर्तन (जैसे स्कोलियोसिस); या जोड़ों की समस्याएँ (जैसे सिकुड़न) ।

इलाज:

- सेरेब्रल पाल्सी का कोई इलाज नहीं है, लेकिन उपचार से इस स्थिति से पीड़ित लोगों के जीवन में सुधार हो सकता है।

अन्य:

- विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस हर साल 6 अक्टूबर को मनाया जाता है।
- 2023 में विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस का विषय “टुगेदर स्ट्रॉन्गर” है।

रोबोटिक्स पर राष्ट्रीय रणनीति**प्रसंग:**

- भारत प्रमुख तकनीकी क्षेत्रों में प्रगति कर रहा है - कृत्रिम बुद्धिमत्ता से लेकर अर्धचालक और रोबोटिक्स तक।
- रोबोटिक्स नीति पर राष्ट्रीय रणनीति विनिर्माण क्षेत्र, उद्योग 4.0 और साइबर-भौतिक प्रणालियों सहित अन्य के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करेगी, इसमें बहुत अधिक प्रभाव पैदा करने की क्षमता है।

उद्देश्य:

- इस क्षमता को भुनाने और रोबोटिक प्रौद्योगिकी के विकास को बढ़ावा देने के लिए, भारत को दुनिया के लिए “रोबोटिक्स हब” के रूप में उभरने में मदद मिलेगी।
- भारत में रोबोटिक प्रौद्योगिकी में घरेलू क्षमताओं का निर्माण सुनिश्चित करना।
- रोबोटिक्स में भारत के वैश्विक नेतृत्व को आगे बढ़ाने के लिए रणनीतिक महत्व के चार क्षेत्रों की भी पहचान की गई है, अर्थात् - विनिर्माण, कृषि, स्वास्थ्य सेवा और राष्ट्रीय सुरक्षा।
- रोबोटिक्स और एआई पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़े सभी लोगों को योगदान देने और इसे एक सफल नीति बनाने के लिए आमंत्रित करना। यह भारत एआई के लिए रणनीतिक योजना और सोच के अनुरूप है।

- एआई-एकीकृत समाज के लाभों को और अधिकतम करने के लिए रोबोटिक्स पर राष्ट्रीय रणनीति को इंडियाएआई के एक ऐसे प्रमुख घटक के रूप में परिकल्पित किया गया है।
- रोबोटिक्स के विकास और अपनाने में भारत को एक वैश्विक नेता के रूप में उभरने में सक्षम बनाने के लिए, रोबोटिक्स पर राष्ट्रीय रणनीति की एक व्यापक, सुसंगत और कुशल तैनाती को श्राष्ट्रीय रोबोटिक्स मिशन के रूप में शुरू करने का प्रस्ताव है।

प्रमुख स्तंभ:

- अनुसंधान और विकास,
- प्रदर्शन एवं परीक्षण,
- व्यावसायीकरण और आपूर्ति श्रृंखला विकास,
- गोद लेना और जागरूकता

लिथियम, नाइओबियम और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों (आरईई) के लिए रॉयल्टी दर को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी



- संसद ने हाल ही में खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2023 पारित किया।
- संशोधन ने नीलामी के माध्यम से निजी क्षेत्र को लिथियम और नाइओबियम सहित छह खनिजों की रियायती बिक्री की अनुमति दी। इन खनिजों को पहले परमाणु खनिजों के रूप में सूचीबद्ध किया गया था।
- संशोधन में अतिरिक्त रूप से निर्धारित किया गया कि केंद्र सरकार 24 आवश्यक और रणनीतिक खनिजों, जैसे लिथियम, नाइओबियम और दुर्लभ पृथ्वी तत्व (आरईई) के लिए खनन पट्टों और मिश्रित लाइसेंस की नीलामी करेगी, जिनमें यूरेनियम या थोरियम शामिल नहीं है।

नई रॉयल्टी दरों को मंजूरी क्यों दी गई है?

- एमएमडीआर अधिनियम की दूसरी अनुसूची विभिन्न खनिजों की रॉयल्टी दरों को सूचीबद्ध करती है।
- वर्तमान में, अधिनियम उस अनुसूची में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किए गए खनिजों के लिए औसत बिक्री मूल्य (एएसपी) के 12% की रॉयल्टी दर स्थापित करता है। यह दर वैश्विक स्तर पर उपयोग किए जाने वाले बेंचमार्क से काफी अधिक है।
- इस वजह से, नई रॉयल्टी दरों को निर्दिष्ट करने के लिए खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की दूसरी अनुसूची में संशोधन किया गया है।
- उपर्युक्त संशोधन भारत की रॉयल्टी दरों को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप लाने और नीलामी के माध्यम से इन खनिजों के व्यावसायिक दोहन की सुविधा प्रदान करने के लिए काम करते हैं, जो केंद्र सरकार या व्यक्तिगत राज्यों द्वारा आयोजित की जा सकती है।

लिथियम, नाइओबियम और दुर्लभ पृथ्वी तत्व (आरईई) क्या हैं?

- **लिथियम:** यह एक क्षार धातु है। यह रिचार्जबल बैटरी में प्रमुख घटकों में से एक है जिसका उपयोग मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक वाहन और पेसमेकर जैसे चिकित्सा उपकरणों में किया जाता है। इसका उपयोग ऊर्जा भंडारण समाधान में भी किया जाता है।
- **दुर्लभ पृथ्वी तत्व:** यह 17-विषम खनिजों के एक समूह को संदर्भित करता है जो स्कैंडियम, येट्रियम और सेरियम जैसे खनिजों को शामिल करता है। इनमें से अधिकांश का उपयोग उत्प्रेरक और चुंबक के रूप में किया जाता है, जिनमें सबसे आम उपयोग मिश्र धातु, कांच, इलेक्ट्रॉनिक्स, पेट्रोलियम निष्कर्षण, हाइब्रिड और ईवीएस के इलेक्ट्रिक मोटर और पवन टरबाइन आदि में होता है।
- **नाइओबियम:** यह एक चांदी जैसी धातु है जिसकी सतह पर ऑक्साइड की परत होती है जो इसे संक्षारण प्रतिरोधी बनाती है।
 - इसका उपयोग स्टेनलेस स्टील सहित मिश्र धातुओं में किया जाता है, ताकि उनकी ताकत में सुधार किया जा सके, खासकर कम तापमान पर।
 - नाइओबियम युक्त मिश्र धातुओं का उपयोग जेट इंजन, इमारतों के लिए बीम और गर्डर्स और तेल और गैस पाइपलाइनों में किया जाता है। इसके अतिचालक गुणों को देखते हुए, इसका उपयोग कण त्वरक और एमआरआई स्कैनर के लिए चुंबक में भी किया जाता है।

- नाइओबियम का मुख्य स्रोत कोलंबाइड खनिज है, जो कनाडा, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और नाइजीरिया जैसे देशों में पाया जाता है।

वेब पोर्टल 'अपना चंद्रयान'



- 'अपना चंद्रयान' एक वेब पोर्टल है जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा छात्रों को चंद्रयान-3 मिशन के बारे में शिक्षित करने के लिए विकसित किया गया था। पोर्टल छात्रों के लिए विभिन्न प्रकार की आकर्षक गतिविधियाँ प्रदान करता है, जिनमें रंगीन किताबें, ऑनलाइन क्विज, जिग्सों पहलियाँ, चित्र निर्माता और ग्राफिक उपन्यास शामिल हैं।
- यह पोर्टल शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग (DoSEL) के तत्वावधान में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) द्वारा विकसित किया गया था। पोर्टल 2023 में लॉन्च किया गया था।
- पोर्टल को तीन अलग-अलग स्तरों पर डिजाइन किया गया है:
 - प्राथमिक स्तर:** यह स्तर 6-8 वर्ष की आयु के छात्रों के लिए है। इसमें रंग पेज, बिंदु से बिंदु मिलान गतिविधियाँ, निर्देशों के साथ रंग कोडिंग आदि शामिल हैं।
 - प्राथमिक स्तर:** यह स्तर 9-12 वर्ष की आयु के छात्रों के लिए है। इसमें चंद्रयान-3 मिशन के बारे में जानकारी प्रदान करने वाली शैक्षिक सामग्री शामिल है।
 - माध्यमिक स्तर:** यह स्तर 13-18 वर्ष की आयु के छात्रों के लिए है। इसमें चंद्रयान-3 मिशन के बारे में अधिक उन्नत जानकारी प्रदान करने वाली शैक्षिक सामग्री शामिल है।

उद्देश्य:

- पोर्टल का उद्देश्य छात्रों को चंद्रयान-3 मिशन के बारे में जानने और अंतरिक्ष अन्वेषण के बारे में उत्साहित होने में मदद करना है। यह पोर्टल एक मूल्यवान संसाधन है जो छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में सीखने में मदद कर सकता है।

लाभ:

- यह छात्रों को चंद्रयान-3 मिशन के बारे में रोचक और आकर्षक तरीके से सीखने में मदद करता है।

- यह छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में अधिक जानने के लिए प्रोत्साहित करता है।
- यह छात्रों को अंतरिक्ष अन्वेषण में भाग लेने के लिए प्रेरित करता है।

इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए "मेड-इन-इंडिया" 2KW डीसी पोर्टेबल चार्जर

- यह लॉन्च भारत में इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में तेजी लाने, आयातित चार्जिंग समाधानों पर वर्तमान निर्भरता को कम करने के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मिशन में योगदान देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- वर्तमान में मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम) द्वारा उपयोग किए जाने वाले पोर्टेबल चार्जर का एक बड़ा हिस्सा आयात किया जाता है और पहले से ही स्थापित प्रोग्राम के साथ आता है। इसलिए, वे वोल्टेज और वर्तमान सेटिंग्स के संदर्भ में अनुकूलन योग्य नहीं हैं।
- चार्जर की उचित कार्यक्षमता सुनिश्चित करने में थर्मल और मैकेनिकल डिजाइन प्रमुख भूमिका निभाते हैं। यह भारत में ईवी के प्रसार में सहायता के लिए मेक-इन-इंडिया चार्जर विकसित करने के महत्व को रेखांकित करता है।
- इस चुनौती का समाधान करने और स्थानीय विनिर्माण को बढ़ाने के लिए, 2KW चार्जर को भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के वित्त पोषण के साथ CEET, IIT मद्रास और औद्योगिक भागीदार फ्लोट्रिक टेक्नोलॉजीज द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है।
- 95% से अधिक की दक्षता और 50 डिग्री सेल्सियस के अधिकतम ऑपरेटिंग परिवेश पर काम करने वाले ये चार्जर ओवर-लोड, ओवर-वोल्टेज, रिवर्स पोलारिटी और इन-बिल्ट ईएमआई/ईएमसी फिल्टर के साथ बनाए गए हैं। चार्जर सुरक्षा मानक IEC 60950-11 को पूरा करने के लिए डिजाइन किए गए हैं।
- चार्जर डिजाइन में बैटरी की आवश्यकताओं के आधार पर अनुकूली चार्जिंग के लिए बैटरी के साथ संचार करने का वैकल्पिक प्रावधान और चार्जिंग से संबंधित मापदंडों की लाइव ट्रैकिंग को सक्षम करने के लिए IoT के लिए हुक भी शामिल हैं।
- व्यक्तिगत ओईएम की आवश्यकता के अनुरूप विनिर्माण की मात्रा के आधार पर पावर आउटपुट सेटिंग्स को अनुकूलित किया जा सकता है। इस तकनीक का बड़े पैमाने पर सफल निर्माण पोर्टेबल चार्जर बाजार में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है।



DAKSH

PRELIMS MENTORSHIP PROGRAM

A RUN WAY TO MAINS

Online/Offline
(Hindi / English Medium)

(By: Amit Jain Sir)

☎ 011-41008973, 8800141518



UPSC CSE 2022 RESULT

I would like to thank the Core IAS team and especially AMIT SIR for his continuous support throughout this long journey. His guidance and grasp about each stage of UPSC CSE is just amazing. My answer writing skills are fully developed by Amit Sir constant support, which helped me to get through this exam.

Thanks & Regards,
JATIN JAIN
AIR 91 in UPSC 2022



JATIN JAIN

AIR-91



काजिंद

भारत-कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास

चाणक्य रक्षा संवाद 2023

- भारतीय सेना सेंटर फॉर लैंड वारफेयर स्टडीज (CLAWS) के साथ साझेदारी में चाणक्य रक्षा संवाद 2023 का आयोजन कर रही है।
- यह सेना द्वारा आयोजित इस प्रकार के कार्यक्रम का पहला संस्करण है और नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है।
- यह दक्षिण एशिया और भारत-प्रशांत में देशों के बीच एक तैयार, उभरते और प्रासंगिक हितधारक के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करने के लिए क्षेत्र में सहयोगात्मक सुरक्षा उपायों के लिए एक रोडमैप तैयार करने पर ध्यान केंद्रित करेगा।

यूरोपीय संघ-भारत नौसैनिक अभ्यास

- यूरोपीय संघ (ईयू) और भारत ने गिनी की खाड़ी में अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया।
- क्षेत्र के समर्थन में नौसैनिक समुद्री सुरक्षा सहयोग को सुदृढ़ करने के प्रयास में, भारत और यूरोपीय संघ के जहाजों ने गिनी की खाड़ी में संयुक्त गतिविधियाँ आयोजित की।

यशस्विनी

- केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से, देश की महिला शक्ति या नारी शक्ति का जश्न मनाने के लिए सीआरपीएफ महिला बाइकर्स के एक समूह "यशस्विनी" के साथ एक क्रॉस-कंट्री बाइक अभियान का आयोजन कर रहा है।
- बल के संदेश "देश के हम हैं रक्षक" को बढ़ावा देने के अलावा, महिला बाइकर्स ने "बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ" के सामाजिक संदेश को भी अपने अभियान में शामिल किया है। वे गर्व से अपनी वर्दी और बैनरों पर "बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ" लोगो प्रदर्शित करेंगे, जिससे पूरे देश में इस उद्देश्य का समर्थन होगा।

सम्प्रीति सैन्य-अभ्यास

भारत और बांग्लादेश के बीच वार्षिक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है और दोनों देशों द्वारा वैकल्पिक रूप से मेजबानी की जाती है।

चक्रवात सैन्य-अभ्यास

- यह एक है जिसमें तीनों सेनाओं, अर्धसैनिक बलों के साथ-साथ कई आपदा प्रतिक्रिया संगठनों, गैर सरकारी संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों की भागीदारी शामिल है।
- 2015 से प्रारंभ
- यह अभ्यास भारतीय सेना, भारतीय नौसेना (आईएन) और भारतीय वायु सेना (आईएएफ) द्वारा बारी-बारी से आयोजित किया गया है।

भारत एनसीएक्स 2023

- राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय ने सरकारी संगठनों और सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास श्रमण एनसीएक्स 2023 के दूसरे संस्करण का आयोजन किया।
- राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास 2023 'भारत एनसीएक्स 2023' का दूसरा संस्करण एक हाइब्रिड अभ्यास के रूप में आयोजित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य समसामयिक साइबर खतरों और साइबर घटनाओं और प्रतिक्रिया से निपटने पर निजी एजेंसियों, सरकारी/महत्वपूर्ण क्षेत्र के संगठनों और सार्वजनिक के वरिष्ठ प्रबंधन और तकनीकी कर्मियों को प्रशिक्षित करना है।

राष्ट्रीय समुद्री खोज एवं बचाव बोर्ड (NMSAR)

- एक वैधानिक निकाय
- 2002 में स्थापित
- जहाजरानी मंत्रालय के अधीन।
- भारतीय खोज और बचाव क्षेत्र (आईएसआरआर) में समुद्री खोज और बचाव (एसएआर) संचालन के समन्वय और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार।



- अध्यक्षता भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) के महानिदेशक द्वारा की जाती है।
- एनएमएसआर बोर्ड में भारतीय नौसेना, नौवहन महानिदेशालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय जैसी अन्य सरकारी एजेंसियों के प्रतिनिधि भी शामिल हैं।

कार्य:

- राष्ट्रीय एसएआर योजनाओं और प्रक्रियाओं का विकास और कार्यान्वयन।
- अन्य एजेंसियों के साथ एसएआर संचालन का समन्वय करना।
- कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करना।
- उपकरणों का रखरखाव।
- एसएआर के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना।

INS सागरध्वनि

- एनपीओएल, कोच्चि द्वारा डिजाइन और विकसित एक समुद्री ध्वनिक अनुसंधान जहाज और जीआरएसई लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से निर्मित।
- यह पोत पिछले 25 वर्षों से व्यापक समुद्री अवलोकन मिशनों और अनुसंधान में संलग्न है।

सागर मैत्री

- DRDO की पहल जो 'क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास (SAGAR)' दृष्टिकोण का समर्थन करती है।
- DRDO ने 'MAITRI (समुद्री और संबद्ध अंतःविषय प्रशिक्षण और अनुसंधान पहल)' नामक एक वैज्ञानिक घटक शुरू किया।

उद्देश्य:

- सामाजिक-आर्थिक पहलुओं के साथ-साथ अधिक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक बातचीत में घनिष्ठ सहयोग को बढ़ावा देना, विशेष रूप से हिंद महासागर रिम (आईओआर) देशों के बीच समुद्री अनुसंधान में।
- आठ आईओआर देशों ओमान, मालदीव, श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और म्यांमार के साथ दीर्घकालिक वैज्ञानिक साझेदारी और सहयोग स्थापित करना।
- यह महासागर अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में आईओआर देशों के साथ दीर्घकालिक सहयोग स्थापित करने पर केंद्रित है।
- सागर मैत्री कार्यक्रम में, आईएनएस सागरध्वनि आईएनएस किस्तना के ट्रैक का अनुसरण करेगा, जिसने 1962-65 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय हिंद महासागर अभियान में भाग लिया था।

सागर कवच

- व्यापक तटीय सुरक्षा अभ्यास
- सभी समुद्री सुरक्षा एजेंसियों को शामिल करते हुए भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित किया गया था

वैश्विक समुद्री भारत शिखर सम्मेलन (जीएमआईएस)

- ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट (GMIS) 2023 मुंबई में आयोजित किया गया।
- यह शिखर सम्मेलन का तीसरा संस्करण था।
- भारत सरकार के बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय (डवचै) द्वारा आयोजित।
- **थीम: एक सतत और समावेशी समुद्री भविष्य का निर्माण**
- **मुख्य मुद्दे:** डीकार्बोनाइजेशन, ऑटोमेशन और डिजिटलाइजेशन, मल्टीमॉडलिज्म, क्रूज पर्यटन, शहरी जल गतिशीलता, समुद्री पेशेवर सेवाएं और समुद्री अनुसंधान, शिक्षा और कौशल विकास।

अन्य बिंदु:

- भारतीय समुद्री नीली अर्थव्यवस्था का खाका 'अमृत काल विजन 2047' का शुभारंभ।
- भारत में अपतटीय पवन ऊर्जा के विकास के लिए MoPSW और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर।

- कपड़ा परिवहन के लिए तटीय शिपिंग को बढ़ावा देने के लिए MoPSW और कपड़ा मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर।
- MoPSW द्वारा एक नए समुद्री कौशल विकास कार्यक्रम की घोषणा।
- MoPSW द्वारा एक नए समुद्री नवाचार कोष का शुभारंभ।

‘इम्फाल’ - प्रोजेक्ट 15बी का तीसरा स्टील्थ विध्वंसक

15बी का तीसरा प्रोजेक्ट स्वदेशी विध्वंसक इम्फाल भारतीय नौसेना को सौंपा गया।

इम्फाल विध्वंसक के बारे में:

- इसे मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल) द्वारा बनाया गया था, और यह प्रोजेक्ट 15बी का तीसरा स्टील्थ विध्वंसक है।
- पिछले दस वर्षों में चालू किए गए कोलकाता श्रेणी (परियोजना 15ए) विध्वंसक को परियोजना 15बी द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है।
- भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो (डब्ल्यूडीबी) ने इस जहाज का निर्माण किया।
- इम्फाल दुनिया के सबसे तकनीकी रूप से उन्नत युद्धपोतों में से एक है।
- इम्फाल एक शक्तिशाली और अनुकूलनीय मंच है जो सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों, जहाज-रोधी मिसाइलों और टॉरपीडो सहित अत्याधुनिक हथियारों और संस्रों से सुसज्जित है।
- इसका विस्थापन 7,400 टन है और इसकी कुल लंबाई 164 मीटर है। इम्फाल 30 समुद्री मील (56 किमी/घंटा) से अधिक की गति से यात्रा करने में सक्षम है।
- जहाज की लगभग 75% सामग्री स्वदेशी लोगों की है। नवंबर 2021 में, P15B (विशाखापत्तनम) का पहला जहाज नौसेना को सौंपा गया था।
- रक्षा मंत्री द्वारा उद्घाटन भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का शुभारंभ किया गया। चर्चाओं, कलाकृति, नृत्य, नाटक, कहानी कहने और प्रदर्शनियों के माध्यम से, दो दिवसीय कार्यक्रम भारत की समृद्ध सैन्य परंपरा और संस्कृति का सम्मान करना चाहता है।
- प्रसिद्ध शिक्षाविदों, पेशेवरों और सक्रिय और सेवानिवृत्त अधिकारियों के साथ पैनल चर्चा के माध्यम से, यह मुख्य रूप से विभिन्न समझ और दृष्टिकोण प्रस्तुत करेगा।
- यह आयोजन “मेक इन इंडिया” और “आत्मनिर्भर भारत” कार्यक्रमों को वास्तविक दुनिया में प्रासंगिकता प्रदान करते हुए भारतीय सैन्य परंपरा, संस्कृति और इतिहास के अध्ययन में रुचि को पुनर्जीवित करने का प्रयास करता है।
- यह सुरक्षा, नीति और विदेशी संबंधों सहित भारत और शेष विश्व को प्रभावित करने वाले कई मौजूदा विषयों पर चर्चा के लिए एक मंच भी प्रदान करता है।
- रक्षा मंत्री द्वारा सैन्य विरासत महोत्सव के उद्घाटन पर प्रोजेक्ट उद्भव की शुरुआत की गई थी।
- प्रोजेक्ट उद्भव, भारतीय सेना और यूएसआई के बीच एक साझेदारी है, जिसका उद्देश्य भारत की पारंपरिक सैन्य मान्यताओं की नींव को फिर से खोजना है।
- शब्द “उद्भव”, जिसका अर्थ है षट्पत्तिष या षट्पत्तिष, हमारे देश के प्राचीन लेखों और ग्रंथों को स्वीकार करता है जो सैकड़ों साल पुराने हैं और इनमें गहन ज्ञान है जो समकालीन सैन्य रणनीति में सहायता कर सकता है।
- परियोजना का लक्ष्य समकालीन सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए एक विशेष, व्यापक रणनीति बनाने के लिए पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक सैन्य रणनीति के साथ जोड़ना है।
- भारतीय सेना ने एक साहसिक पहल शुरू की है जिसका उद्देश्य पारंपरिक सैन्य शिक्षाशास्त्र को अत्याधुनिक ज्ञान के साथ जोड़ना है।

पहला सैन्य विरासत महोत्सव



गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव (जीएमसी)

- गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव (जीएमसी) नौसेना युद्ध कॉलेज, गोवा के तत्वावधान में भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित एक त्रिवार्षिक समुद्री सुरक्षा सम्मेलन है। यह कॉन्क्लेव हिंद महासागर क्षेत्र (आईओआर) में प्रमुख समुद्री सुरक्षा चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा करने के लिए दुनिया भर के वरिष्ठ समुद्री सुरक्षा चिकित्सकों, विद्वानों और उद्योग जगत के नेताओं को एक साथ लाता है।

- GMC का विषय “आईओआर में समुद्री सुरक्षा: चुनौतियों और अवसरों के माध्यम से नेविगेट करना” है।
- जीएमसी में भारत और आईओआर के अन्य देशों के बीच कई समुद्री सुरक्षा समझौतों और समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है।
- जीएमसी भारतीय नौसेना की आउटरीच पहल में एक महत्वपूर्ण घटना है और इसे आईओआर में समुद्री सुरक्षा साझेदारी और सहयोग बनाने के लिए एक मंच के रूप में देखा जाता है।
- समुद्री सुरक्षा चर्चाओं के अलावा, जीएमसी में भारतीय नौसेना की स्वदेशी जहाज निर्माण क्षमताओं को प्रदर्शित करने वाली “मेक इन इंडिया” प्रदर्शनी भी आयोजित की जाती है। प्रदर्शनी में आने वाले आगंतुकों को स्वदेशी

युद्धपोतों और डीप सबमर्जेस रेस्क्यू वेसल (डीएसआरवी) की क्षमताओं को देखने का भी अवसर मिलेगा।

विशेषताएँ:

- आईओआर में उभरते समुद्री सुरक्षा खतरे
- समुद्री डोमेन जागरूकता और निगरानी
- समुद्री सुरक्षा सहयोग एवं समन्वय
- समुद्री कानून प्रवर्तन
- समुद्री बुनियादी ढांचे की सुरक्षा
- समुद्री साइबर सुरक्षा
- समुद्री प्रदूषण और पर्यावरण संरक्षण



CURRENT AFFAIRS

Pre Cum Mains 2024

Online/Offline

(Hindi / English Medium)

(By: Amit Jain Sir)

- Co-related with static portion
- PYQ Linkage
- Short, Crisp & Concise notes.

2022

22
Questions
In Prelims

2023

31
Questions
In Prelims

2024

For
You

©011-41008973, 8800141518





‘स्थिति धारक’ प्रमाणपत्र

- केंद्रीय वाणिज्य मंत्री ने विदेश व्यापार नीति 2023 के तहत सिस्टम-आधारित स्वचालित ‘स्टेटस होल्डर’ प्रमाणपत्र का अनावरण किया।

क्यों?

- लेनदेन लागत को कम करने और व्यापार करने में आसानी में सुधार लाने के उद्देश्य से, केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भारतीय निर्यातकों को विश्वसनीयता देने की प्रणाली को स्वचालित कर दिया है।
- विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2023 के तहत स्टेटस होल्डर प्रमाणपत्र उन निर्यातकों को दिए जाते हैं जिन्होंने निर्यात प्रदर्शन का एक निश्चित स्तर हासिल किया है।

लाभ:

- एफटीपी के तहत सरलीकृत प्रक्रियाएं
- स्व-घोषणा के आधार पर प्राथमिकता कस्टम क्लियरेंस
- बैंकों के माध्यम से दस्तावेजों की अनिवार्य बातचीत से छूट
- एफटीपी योजनाओं के लिए बैंक गारंटी दाखिल करने से छूट

भारतीय फार्माकोपिया आयोग

यह क्या है?

- भारत में दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने वाली एक स्वायत्त संस्था। यह उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा की रक्षा करने और भारतीय दवा उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने में मदद करता है।
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत।
- 2009 में स्थापित।

उद्देश्य:

- भारत में दवाओं के मानकों की आधिकारिक पुस्तक, इंडियन फार्माकोपिया (आईपी) को प्रकाशित करना और उसका रखरखाव करना।

कार्य:

- हर्बल दवाओं के लिए मानकों का विकास और रखरखाव।
- आईपी और फार्मास्युटिकल गुणवत्ता नियंत्रण पर प्रशिक्षण प्रदान करना।

- फार्मास्युटिकल गुणवत्ता नियंत्रण पर अनुसंधान करना।
- फार्मास्युटिकल गुणवत्ता नियंत्रण पर अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करना।

लाभ:

- भारत में दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करता है।
- उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा की रक्षा करता है।
- भारतीय दवा उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देता है।
- फार्मास्युटिकल्स में व्यापार को सुगम बनाता है।
- फार्मास्युटिकल गुणवत्ता नियंत्रण में अनुसंधान और विकास का समर्थन करता है।

लद्दाख में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना



- कैबिनेट ने लद्दाख में 13 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर (जीईसी) चरण-II - अंतर-राज्य ट्रांसमिशन सिस्टम (आईएसटीएस) को मंजूरी दी।
- कार्यान्वयन एजेसी- पावरग्रिड।
- इस ऊर्जा के लिए ट्रांसमिशन लाइन हिमाचल प्रदेश और पंजाब से होकर हरियाणा के कैथल तक जाएगी, जहां इसे राष्ट्रीय ग्रिड के साथ एकीकृत किया जाएगा।
- लेह में इस परियोजना से मौजूदा लद्दाख ग्रिड तक एक इंटर-कनेक्शन की भी योजना बनाई गई है ताकि लद्दाख को विश्वसनीय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

- इसे जम्मू-कश्मीर को बिजली प्रदान करने के लिए लेह-अलुस्टेंग-श्रीनगर लाइन से भी जोड़ा जाएगा।

लाभ:

- देश की दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा का विकास करना।
- कार्बन पदचिह्न को कम करके पारिस्थितिक रूप से टिकाऊ विकास को बढ़ावा देता है।
- बिजली और अन्य संबंधित क्षेत्रों में, विशेष रूप से लद्दाख क्षेत्र में कुशल और अकुशल दोनों कर्मियों के लिए बड़े प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
- 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन से 500 गीगावाट स्थापित बिजली क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करने में योगदान देगा।

भारत-टेक्स 2024

- इवेंट “भारत-टेक्स 2024” 26-29 फरवरी, 2024 तक नई दिल्ली में होगा।
- प्रदर्शनियों, शैक्षिक सत्रों और खरीदार बैठकों के साथ, “भारत टेक्स 2024” सबसे बड़ा कपड़ा आयोजन होने की उम्मीद है।
- इसका उद्देश्य फाइबर से लेकर फैशन तक, संपूर्ण कपड़ा मूल्य श्रृंखला में भारत की क्षमताओं को उजागर करना है।
- भारत की संपूर्ण कपड़ा मूल्य श्रृंखला की स्थिति और प्रदर्शन के अलावा, भारत-टेक्स 2024 फैशन, पारंपरिक शिल्प और स्थिरता पहल में देश की ताकत को भी उजागर करेगा।

एनएलसी इंडिया लिमिटेड द्वारा एनएलसी इंडिया ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (NIGEL) नामक एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी को शामिल जाना

- कोयला मंत्रालय के तहत, एनएलसी इंडिया लिमिटेड एक नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है।
- सभी नवीकरणीय ऊर्जा पहलों को अपना छफ्टम्स की मुख्य प्राथमिकता है।
- केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की 2030 ऑप्टिमल एनर्जी मिक्स रिपोर्ट के अनुसार, ग्रिड पर एक बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) होगी जिसका आकार लगभग 41.65 गीगावाट होगा।

नवरत्न उद्यम

- सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई को नवरत्न कंपनी के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए निवल मूल्य, शुद्ध लाभ, उत्पादन की कुल लागत, कुल श्रम लागत, सेवाओं की कुल लागत, नियोजित पूंजी और पीबीडीआईटी (मूल्यहास से पहले लाभ, ब्याज और कर) की श्रेणियों में 100 में से कम से कम 60 अंक प्राप्त करने चाहिए।
- इसके अतिरिक्त, यह एक मिनीरत्न होनी चाहिए।
- निगम के लिए चार स्वतंत्र बोर्ड सदस्य होने चाहिए।
- नवरत्न कंपनियों को स्पष्ट सरकारी सहमति के अनुरोध के बिना 1,000 करोड़ रु. तक निवेश करने की अनुमति है।
- वे किसी विशेष परियोजना पर अपनी निवल संपत्ति का 15% या पूरे वर्ष के दौरान अपनी निवल संपत्ति का 30% भी निवेश कर सकते हैं, लेकिन ₹1,000 करोड़ की सीमा से अधिक नहीं।

नैनो-डीएपी



नैनो-डीएपी क्या है?

- नैनो-डीएपी से गैर-यूरिया उर्वरकों पर वार्षिक सब्सिडी कम होने और मूल्य श्रृंखला में शामिल सभी लोगों को महत्वपूर्ण लाभ मिलने की उम्मीद है।
- नैनो-डीएपी को सरकार सब्सिडी कम करने और पौधों के रसायनों के कुशल उपयोग को बढ़ावा देने के लिए बढ़ावा दे रही है।
- यूरिया के बाद, डीएपी भारत में दूसरा सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला उर्वरक है। लगभग 10-12.5 मिलियन टन की अनुमानित वार्षिक खपत में से, स्थानीय उत्पादन लगभग 4-5 मिलियन टन है, जबकि बाकी आयात किया जाता है।
- नैनो-डीएपी (डाई-अमोनियम फॉस्फेट) भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड (इफको) द्वारा विकसित एक नैनो-प्रौद्योगिकी-आधारित कृषि-आगत है।

यह महत्वपूर्ण क्यों है?

- पारंपरिक दानेदार बैग में मौजूद 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस की तुलना में इसमें 8% नाइट्रोजन और 16% फास्फोरस होगा।
- नैनो-डीएपी की 500 मिलीलीटर की बोतल नियमित डीएपी के 50 किलोग्राम बैग के बराबर है। नैनो-डीएपी की एक बोतल की कीमत ₹600 (बिना सब्सिडी के) है, जबकि पारंपरिक डीएपी की कीमत घ. 3,350 प्रति बैग (उर्वरक सब्सिडी के साथ) है।

लाभ:

- अधिक फसल उपज
- किसानों की आय में वृद्धि
- पौष्टिक भोजन
- पर्यावरण के अनुकूल
- रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग में कमी
- भंडारण और परिवहन में आसान
- सब्सिडी के बोझ में कमी

कार्यस्थल की दक्षता बढ़ाना

- कार्यस्थल की दक्षता बढ़ाना सभी आकार के व्यवसायों के लिए आवश्यक है। अधिक कुशल कार्यक्षेत्र बनाकर, व्यवसाय उत्पादकता में सुधार कर सकते हैं, लागत कम कर सकते हैं और कर्मचारियों का मनोबल बढ़ा सकते हैं।
- कार्यस्थल की दक्षता बढ़ाना एक सतत प्रक्रिया है। अपने कार्यक्षेत्र की नियमित रूप से समीक्षा करना और उन क्षेत्रों की पहचान करना महत्वपूर्ण है जहां आप सुधार कर सकते हैं। छोटे-छोटे बदलाव करने के लिए समय निकालकर, आप अपने और अपनी टीम के लिए अधिक कुशल और उत्पादक कार्यक्षेत्र बना सकते हैं।

कार्यस्थल की दक्षता बढ़ाने के लिए व्यवसाय क्या कर सकते हैं:

- **अपना कार्यक्षेत्र व्यवस्थित करना।** अव्यवस्थित कार्यक्षेत्र मन को अव्यवस्थित बना सकता है। अपने कार्यक्षेत्र को व्यवस्थित करने के लिए समय निकालकर, आप विकर्षणों को कम कर सकते हैं और अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इसमें आपके डेस्क को अव्यवस्थित करना, अनावश्यक वस्तुओं को दूर रखना और महत्वपूर्ण दस्तावेजों के लिए फाइलिंग सिस्टम बनाना शामिल हो सकता है।
- **एर्गोनोमिक फर्नीचर में निवेश करना।** एर्गोनोमिक फर्नीचर आपके शरीर को सहारा देने और थकान को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है। इससे आराम और उत्पादकता में सुधार हो सकता है। एर्गोनोमिक फर्नीचर चुनते समय, अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं पर विचार करना सुनिश्चित करें।
- **सही प्रकाश व्यवस्था चुनना।** प्रकाश आपके मूड और उत्पादकता पर बड़ा प्रभाव डाल सकता है। बहुत अधिक रोशनी कठोर और ध्यान भटकाने वाली हो सकती है, जबकि बहुत कम रोशनी आपको थका हुआ और सुस्त महसूस करा सकती है। ऐसा प्रकाश समाधान चुनें जो बहुत उज्ज्वल या बहुत मंद हुए बिना पर्याप्त रोशनी प्रदान करता हो।
- **ब्रेक को प्रोत्साहित करना।** यह विपरीत लग सकता है, लेकिन ब्रेक लेने से वास्तव में आपकी उत्पादकता में सुधार हो सकता है। जब आप बिना ब्रेक लिए लंबे समय तक काम करते हैं तो आपका दिमाग और शरीर थकने लगता है। इससे गलतियाँ हो सकती हैं और उत्पादकता में कमी आ सकती है। उठने और घूमने के लिए, या कुछ ताजी हवा के लिए बाहर जाने के लिए दिन भर में छोटे-छोटे ब्रेक लें।
- **अपने लाभ के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना।** ऐसे कई तकनीकी उपकरण हैं जो आपके काम को अधिक कुशल बनाने में आपकी मदद कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप अपनी प्रगति और समय सीमा को ट्रैक करने के लिए प्रोजेक्ट प्रबंधन सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकते हैं, या आप अपनी टीम के सदस्यों के साथ संपर्क में रहने के लिए संचार उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं।





राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह

- 69वां वन्यजीव सप्ताह, भारत में वन्यजीव संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम।
- इस वर्ष की थीम, “वन्यजीव संरक्षण के लिए साझेदारी”, देश की समृद्ध जैव विविधता की रक्षा और संरक्षण के लिए आवश्यक सहयोगात्मक प्रयासों को दर्शाती है।
- राष्ट्रीय प्राणी उद्यान द्वारा शुरू किया गया

मील का पत्थर:

- वन्यजीव सप्ताह से जुड़े सबसे उल्लेखनीय मील के पत्थर में से एक 1981 के उत्सव के दौरान दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान को जनता के लिए खोलना है। इस महत्वपूर्ण निर्णय ने पर्यटकों और प्रकृति प्रेमियों को प्रतिष्ठित हंगुल या कश्मीर बारहसिंगा सहित पार्क की लुभावनी जैव विविधता का पता लगाने की अनुमति दी। दाचीगाम के अद्वितीय वन्य जीवन के संपर्क ने क्षेत्र की प्राकृतिक विरासत की अधिक समझ और सराहना में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

पेसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन (PATA)

- पेसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन (PATA) एक गैर-लाभकारी सदस्यता संघ है जो एशिया प्रशांत क्षेत्र से और उसके भीतर यात्रा और पर्यटन के जिम्मेदार विकास के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है।
- PATA सदस्यता में सरकारें, राज्य और शहर पर्यटन निकाय, अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस और हवाई अड्डे, आतिथ्य संगठन, शैक्षणिक संस्थान और एशिया प्रशांत और उससे आगे की सैकड़ों यात्रा उद्योग कंपनियां शामिल हैं।
- PATA एशिया प्रशांत क्षेत्र में यात्रा और पर्यटन पर एक अग्रणी संस्था है। एसोसिएशन उद्योग के जिम्मेदार विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकारों, व्यवसायों और अन्य हितधारकों के साथ मिलकर काम करता है। PATA अपने सदस्यों और समग्र रूप से यात्रा और पर्यटन उद्योग के हितों की वकालत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- PATA एशिया प्रशांत क्षेत्र में यात्रा और पर्यटन उद्योग से जुड़े किसी भी व्यक्ति के लिए एक मूल्यवान संसाधन है। एसोसिएशन अपने सदस्यों को कई प्रकार की सेवाएँ और संसाधन प्रदान करता है जो उन्हें अपने व्यवसाय को बढ़ाने और उद्योग के जिम्मेदार विकास को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं।

मिशन: पूरे प्रशांत एशिया क्षेत्र में यात्रा और पर्यटन उद्योग के विकास को बढ़ाना, प्रोत्साहित करना और सहायता करना।

सेवाएँ और संसाधन:

- अनुसंधान और सांख्यिकी
- वकालत और प्रतिनिधित्व
- नेटवर्किंग और घटनाएँ
- प्रशिक्षण और शिक्षा

इकोमार्क योजना

एक स्वैच्छिक उत्पाद लेबलिंग योजना जो पर्यावरण-अनुकूल उत्पादों की पहचान करती है।

यह भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रशासित है, जो भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है।



पात्रता:

किसी उत्पाद को बीआईएस द्वारा निर्दिष्ट कुछ पर्यावरणीय मानदंडों को पूरा करना होगा।

ये मानदंड उत्पाद श्रेणी के आधार पर भिन्न-भिन्न होते हैं।

लाभ:

- यह उपभोक्ताओं को पर्यावरण-अनुकूल उत्पादों की पहचान करने में मदद करता है।
- यह व्यवसायों को पर्यावरण-अनुकूल उत्पाद बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है।
- यह उपभोक्ता उत्पादों के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करता है।

हरित क्रेडिट कार्यक्रम (जीसीपी)

यह क्या है?

- जीसीपी एक बाजार-आधारित तंत्र है जिसका उद्देश्य व्यक्तियों, संगठनों और उद्योगों को स्वैच्छिक पर्यावरणीय कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित करना है।

- प्रतिभागी उन गतिविधियों को करने के लिए क्रेडिट अर्जित कर सकते हैं जो उनके पर्यावरणीय प्रभाव को कम करती हैं।
- जीसीपी एक **स्वैच्छिक कार्यक्रम** है, लेकिन इसके व्यक्तियों, व्यवसायों और सरकारी एजेंसियों सहित प्रतिभागियों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए आकर्षक होने की उम्मीद है।
- फिर इन क्रेडिटों का घरेलू बाजार मंच पर व्यापार किया जा सकता है और उन व्यक्तियों और संगठनों द्वारा खरीदा जा सकता है जो अपने स्वयं के पर्यावरणीय प्रभाव की भरपाई करना चाहते हैं।
- जीसीपी ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने, पानी की गुणवत्ता में सुधार और जैव विविधता की रक्षा करने में मदद कर सकता है।

लाभ:

- स्वैच्छिक पर्यावरणीय कार्यों को प्रोत्साहित करता है।
- ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करता है।
- पानी की गुणवत्ता में सुधार करता है।
- जैव विविधता की रक्षा करता है।
- पर्यावरण सेवाओं के लिए एक बाजार तैयार करता है।
- सतत विकास को बढ़ावा देता है।

लिटिल आइस एज (LIA)

नया अध्ययन:

- सामान्यतः लिटिल आइस एज (एलआईए) की विशेषता समान रूप से ठंडे और शुष्क मौसम के साथ कम मानसूनी

वर्षा मानी जाती थी, जिसे नवीनतम अध्ययन द्वारा चुनौती दी गई है, जो **वर्षा प्रतिरूप में पर्याप्त उतार-चढ़ाव का खुलासा** करता है।

- अध्ययन ने वर्ष 1219 और 1942 के बीच पश्चिमी घाट से पराग आधारित वनस्पति गतिशीलता, वर्तमान जलवायु परिवर्तन और मानसूनी परिवर्तनशीलता का पुनर्निर्माण किया।



- अनुसंधान क्षेत्र में मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय नम/अर्ध-सदाबहार/शुष्क वन देखे गए।
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वतंत्र संस्थान, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोसाइंसेज (बीएसआईपी) ने शोध किया।

लघु हिमयुग क्या है?

- लिटिल आइस एज (LIA) क्षेत्रीय शीतलन की अवधि थी, जो विशेष रूप से उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र में 16वीं और 19वीं शताब्दी (1671 CE - 1942 CE) के बीच देखी गई थी।
- 1300 से 1850 की एक वैकल्पिक समयावधि भी प्रस्तावित की गई है।
- यह वैश्विक स्तर का सच्चा हिमयुग नहीं है।

OTHER PYQ BOOKLETS

<p>ENVIRONMENT & ECOLOGY 2011-2023 PYQ</p> <p>011-41008973, 8800141518</p>	<p>Economy 2011-2023 PYQ</p> <p>011-41008973, 8800141518</p>	<p>SCHEME & POLICY 2011-2023 PYQ</p> <p>011-41008973, 8800141518</p>	<p>THE CORE IAS Science & TECHNOLOGY (PYQ-2011-2023)</p> <p>011-41008973, 8800141518</p>
<p>THE CORE IAS International Relations 2011-2023 PYQ</p> <p>011-41008973, 8800141518</p>	<p>THE CORE IAS Indian Polity PYQ 2011-2023</p> <p>011-41008973, 8800141518</p>	<p>THE CORE IAS HISTORY 2011-2023 PYQ</p> <p>011-41008973, 8800141518</p>	<p>THE CORE IAS GEOGRAPHY (PYQ-2011-2023)</p> <p>011-41008973, 8800141518</p>

103, B-5/6 Floor, Himalika Commercial Complex Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 09

53/18, Old Rajinder Nagar, New Delhi, 110060

📞 011-41008973, 8800141518, 9873833547



इतिहास

पार्वती कुंड और जागेश्वर मंदिर (कुमाऊं क्षेत्र, उत्तराखंड)

- प्रसंग:** प्रधान मंत्री ने लोगों को उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में पार्वती कुंड और जागेश्वर मंदिरों की प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक महत्व पर जोर देते हुए जाने के लिए प्रोत्साहित किया है।
- उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र के जिला अल्मोडा में स्थित जागेश्वर एक हिंदू तीर्थस्थल शहर है जो 7वीं से 14वीं शताब्दी के 125 ऐतिहासिक मंदिरों के संग्रह के लिए प्रसिद्ध है, जिनमें से अधिकांश का निर्माण और जीर्णोद्धार कत्यूरी राजवंश के राजाओं द्वारा किया गया था। इनमें से कई मंदिर भगवान शिव का सम्मान करते हैं, लेकिन कुछ मंदिर अन्य देवताओं को भी समर्पित हैं।
 - लिंग और स्कंद पुराण के अनुसार, जागेश्वर भगवान शिव की पूजा का जन्मस्थान था, जिससे यह एक महत्वपूर्ण पूजा स्थल बन गया। इसके अलावा, लकुलीश शैववाद, एक पुनरुत्थानवादी संप्रदाय जो भगवान शिव का सम्मान करता है, का केंद्र इस क्षेत्र में था।
 - महा शिवरात्रि मेला और जागेश्वर मानसून महोत्सव जैसे धार्मिक उत्सव भी वहां आयोजित किए जाते हैं। मंदिर दक्षिण/मध्य भारतीय और उत्तर भारतीय नागर स्थापत्य शैली का मिश्रण प्रदर्शित करते हैं।
 - पार्वती कुंड:** लगभग 5,338 फीट की ऊंचाई पर स्थित, यह वह स्थान माना जाता है जहां भगवान शिव और देवी पार्वती ने ध्यान किया था।



कटि बिहू

- इसे कोंगाली बिहू के नाम से भी जाना जाता है।
- यह एक असमिया त्योहार है जो चावल के पौधों के स्थानांतरण के समय को चिह्नित करने के लिए मनाया जाता है।
- असम के अन्य बिहू त्योहारों की तरह, यह भी कृषि से जुड़ा हुआ है।
- इस दिन तुलसी के पौधे की पूजा की जाती है।
- असम में अन्य दो बिहू त्योहार हैं:
 - भोगाली या माघ बिहू (जनवरी में मनाया जाता है)।
 - रोंगाली या बोहाग बिहू (अप्रैल में मनाया जाता है)।

सर्वोत्तम पर्यटन ग्राम

- UNWTO द्वारा गुजरात के धोडों गांव को शसर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार दिया गया।



भारतीय राजनीति

राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड



राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड (एनटीबी) भारत सरकार द्वारा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत 2023 में स्थापित एक वैधानिक निकाय है।

स्थापना क्यों?

- देश में हल्दी और हल्दी उत्पादों के विकास और प्रचार के लिए एक शीर्ष निकाय।
- एनटीबी से हल्दी क्षेत्र की वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने और दुनिया भर में हल्दी और हल्दी उत्पादों की जागरूकता और खपत बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है।

कार्य:

- हल्दी क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना
- हल्दी उत्पादों के लिए मूल्य संवर्धन और बाजार पहुंच की सुविधा प्रदान करना
- हल्दी के स्वास्थ्य और कल्याण लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ रही है
- हल्दी एवं हल्दी उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना
- हल्दी क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए अन्य सरकारी एजेंसियों और हितधारकों के साथ समन्वय करना

संरचना:

- यह एक निदेशक मंडल द्वारा शासित होता है, जिसकी अध्यक्षता केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष करता है। बोर्ड में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, फार्मास्यूटिकल्स विभाग, कृषि और किसान कल्याण

विभाग, मसाला बोर्ड और अन्य संबंधित संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हैं।

- इसका मुख्यालय कोच्चि, कर्नाटक में है और इसके क्षेत्रीय कार्यालय अन्य प्रमुख हल्दी उत्पादक राज्यों में हैं।

पहल:

- भोजन एवं पेय पदार्थों में हल्दी के उपयोग को बढ़ावा देना।
- नए हल्दी-आधारित उत्पादों, जैसे पौष्टिक-औषधीय पदार्थों (न्यूट्रास्यूटिकल्स) और सौंदर्य-प्रसाधनों (कॉस्मीस्यूटिकल्स) का विकास करना।
- नए बाजारों में हल्दी और हल्दी उत्पादों का निर्यात बढ़ाना।
- किसानों को उनकी उत्पादकता और आय में सुधार करने में सहायता करना।
- हल्दी की नई किस्मों और खेती के तरीकों पर अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना।

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए)

- विद्युत मंत्रालय के अधीन वैधानिक संगठन।
- विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत।

कार्य:

- राष्ट्रीय विद्युत नीति से संबंधित मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह देना।
- विद्युत संयंत्रों, विद्युत लाइनों और ग्रिड कनेक्टिविटी के निर्माण के लिए तकनीकी मानक निर्दिष्ट करना।
- बिजली के उत्पादन, पारेषण, वितरण और व्यापार को प्रभावित करने वाले मामलों में अनुसंधान को बढ़ावा देना।

मेरा युवा भारत

- 15-29 वर्ष की आयु वर्ग के युवाओं के लाभ के लिए एक स्वायत्त निकाय।
- यह युवा विकास और युवा-नेतृत्व वाले विकास के लिए प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित एक व्यापक सक्षम तंत्र के रूप में काम करेगा और युवाओं को उनकी आकांक्षाओं को साकार करने और सरकार के पूरे स्पेक्ट्रम में विकसित भारत का निर्माण करने के लिए समान पहुंच प्रदान करेगा।

उद्देश्य:

- अलग-अलग शारीरिक संपर्क से कार्यक्रम-संबंधी कौशल में बदलाव करके अनुभवात्मक शिक्षा के माध्यम से नेतृत्व कौशल में सुधार करना।
- इसे युवा विकास के लिए एक संपूर्ण सरकारी मंच बनाना।
- युवाओं को सामाजिक नवप्रवर्तक और समुदायों में नेता बनाने के लिए उनमें अधिक निवेश करना।
- युवाओं के नेतृत्व वाले विकास पर सरकार का ध्यान केंद्रित करना और युवाओं को विकास का “सक्रिय चालक” बनाना, न कि केवल “निष्क्रिय प्राप्तकर्ता”।

जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ)**यह क्या है?**

- जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 के तहत स्थापित गैर-लाभकारी संगठन हैं। डीएमएफ को खनन कंपनियों द्वारा राज्य सरकारों को भुगतान की गई रॉयल्टी के 10% के योगदान से वित्त पोषित किया जाता है।

उद्देश्य:

- खनन से प्रभावित व्यक्तियों एवं क्षेत्रों के हित एवं लाभ के लिए कार्य करना
- खनन से प्रभावित क्षेत्रों के सतत विकास को बढ़ावा देना
- सुनिश्चित करना कि खनन के लाभ खनन से प्रभावित लोगों और क्षेत्रों के साथ समान रूप से साझा किए जाएं
- सड़क, स्कूल और अस्पताल जैसी बुनियादी सुविधाओं का विकास
- स्वास्थ्य एवं स्वच्छता सुविधाओं में सुधार
- शिक्षा एवं कौशल विकास को बढ़ावा देना
- पर्यावरण का संरक्षण एवं पुनर्स्थापन
- खनन क्षेत्र का सतत विकास
- स्कूलों, अस्पतालों और सड़कों का निर्माण
- पेयजल एवं स्वच्छता सुविधाओं का प्रावधान
- शिक्षा एवं कौशल विकास को बढ़ावा देना
- वनीकरण और पर्यावरण बहाली परियोजनाएँ
- आजीविका सृजन परियोजनाओं के माध्यम से खनन क्षेत्रों का सतत विकास

प्रशासन:

- जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक प्रबंधन बोर्ड।

- प्रबंधन बोर्ड में राज्य सरकार, खनन कंपनियों और स्थानीय समुदाय के प्रतिनिधि शामिल हैं।

डिजिटल DARPG

- “डिजिटल DARPG” थीम के तहत प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने अखिल भारतीय एकीकृत सेवा वितरण पोर्टलों को बढ़ावा देने, सार्वजनिक शिकायतों में लंबित मामलों को कम करने, लोक शिकायतों के प्रभावी निवारण के लिए एआई/उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने, संधारणीय प्रथाओं को बढ़ावा देने और कार्यालय में स्वच्छता और कुशल रिकॉर्ड प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान 3.0 के तहत कई महत्वपूर्ण कदम उठाए।

विमान नियम, 1937 में संशोधन

- विमान नियम, 1937 में संशोधन उद्योग में हितधारकों के साथ पर्याप्त परामर्श का परिणाम है, जिसका उद्देश्य मौजूदा नियामक सुरक्षा और सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने के लिए आवश्यक सुधार उपाय प्रदान करना है। ये संशोधन भारत के विमानन नियमों को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) के मानकों और अनुशासित प्रथाओं (SARPs) और अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ संरेखित करते हैं।
- विमान नियम, 1937 में संशोधन का एक मुख्य आकर्षण नियम 39सी का संशोधन है। इस संशोधन के तहत, एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस (एटीपीएल) और वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस (सीपीएल) धारकों के संबंध में लाइसेंस की वैधता पांच साल से बढ़ाकर दस साल कर दी गई है। इस बदलाव से पायलटों और डीजीसीए जैसे विमानन प्राधिकरणों पर प्रशासनिक बोझ कम होने की उम्मीद है, जिससे अधिक सुव्यवस्थित और कुशल लाइसेंसिंग प्रक्रिया को बढ़ावा मिलेगा।

- विमान नियम, 1937 में संशोधन नियम 66 के तहत महत्वपूर्ण बदलाव पेश करता है, जो हवाई अड्डे के आसपास “झूठी रोशनी” के प्रदर्शन से संबंधित चिंताओं को संबोधित करता है। यह अद्यतन स्पष्ट करता है कि “प्रकाश” शब्द में लालटेन रोशनी, इच्छा पतंग और लेजर रोशनी शामिल हैं। ऐसी रोशनी प्रदर्शित करने वालों पर सरकार का अधिकार क्षेत्र हवाई अड्डे के आसपास 5 किलोमीटर से 5 समुद्री मील तक बढ़ा दिया गया है।
- इसके अलावा, यह स्पष्ट किया गया है कि सरकार के पास ऐसी रोशनी प्रदर्शित करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार है जो विमान के सुरक्षित संचालन को बाधित करते हैं या संचालन दल के लिए खतरा पैदा करते हैं। यदि ऐसी लाइटें 24 घंटे तक अप्राप्य रहती हैं, तो सरकार को उस स्थान में प्रवेश करने और उन्हें बुझाने का अधिकार है। साथ ही, मामले को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत कानूनी कार्रवाई के लिए संबंधित पुलिस स्टेशन को सूचित किया जाएगा। जब देखे गए प्रकाश का स्रोत अज्ञात होता है या यदि वह स्थान बदलता है, तो

हवाईअड्डा या एयरलाइन ऑपरेटर संभावित आपराधिक कार्यवाही शुरू करते हुए घटना की तुरंत स्थानीय पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट करने के लिए बाध्य है।

- विदेशी लाइसेंसों के सत्यापन के लिए नियम 118 को अनावश्यक होने के कारण हटा दिया गया है। यह परिवर्तन विमानन क्षेत्र की उभरती जरूरतों के साथ नियमों को संरेखित करने का प्रतीक है।
- एयर टैफिक कंट्रोलर लाइसेंस धारकों के लिए निरंतर क्षमता सुनिश्चित करते हुए नवीनता और योग्यता आवश्यकताओं को उदार बनाने के लिए एक खंड अनुसूची III के तहत जोड़ा गया है। यह परिवर्तन सीमित गतिविधियों या देखने के घंटों के साथ स्थितियों को समायोजित करने के लिए अधिक लचीलापन प्रदान करता है, एयर टैफिक कंट्रोलर लाइसेंस धारकों को आपात स्थिति सहित कम से कम दस घंटे के सिम्युलेटेड अभ्यास पूरे करने होंगे। इसके बाद, उन्हें इन अभ्यासों को शुरू करने के लगातार दस दिनों के भीतर अपनी संबंधित रेटिंग के लिए कौशल मूल्यांकन से गुजरना होगा।





इंडियास्किल्स 2023-24

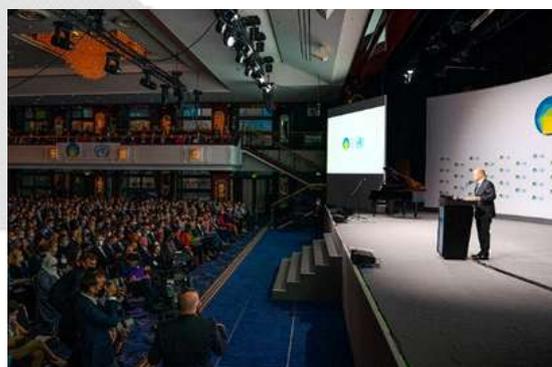
- इंडियास्किल्स 2023-24 एक राष्ट्रीय कौशल विकास प्रतियोगिता है जो 4-10 अगस्त, 2023 तक उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो सेंटर में आयोजित की जाएगी। प्रतियोगिता में विनिर्माण, निर्माण, आईटी और स्वास्थ्य देखभाल सहित उद्योगों की एक विस्तृत श्रृंखला में 50 से अधिक कौशल शामिल होंगे।
- इंडियास्किल्स 2023-24 इंडियास्किल्स वर्ल्डस्किल्स प्रतियोगिता का अग्रदूत है, जो दुनिया की सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय कौशल प्रतियोगिता है। इंडियास्किल्स 2023-24 के विजेता वर्ल्डस्किल्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, जो 2024 में पेरिस, फ्रांस में आयोजित किया जाएगा।
- इंडियास्किल्स प्रतियोगिता का आयोजन कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) द्वारा राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के सहयोग से किया जाता है। यह प्रतियोगिता 18 से 25 वर्ष की आयु के भारतीय नागरिकों के लिए खुली है।
- इंडियास्किल्स प्रतियोगिता भारत सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है क्योंकि यह युवाओं के बीच कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देने में मदद करता है। यह प्रतियोगिता भारतीय कार्यबल के कौशल को पहचानने और विकसित करने में भी मदद करती है, जो देश की आर्थिक वृद्धि के लिए आवश्यक है।
- इंडियास्किल्स 2023-24 प्रतियोगिता युवा भारतीयों के लिए अपने कौशल का प्रदर्शन करने और देश में सर्वश्रेष्ठ के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने का एक शानदार अवसर है। यह प्रतियोगिता युवा भारतीयों के लिए नए कौशल सीखने और अपनी क्षमता विकसित करने का एक शानदार अवसर है।

उद्देश्य:

- **रोजगारपरक कौशल को बढ़ावा देना:** कार्यक्रम बाजार की जरूरतों के अनुरूप रोजगार योग्य कौशल विकसित करने के महत्व को रेखांकित करता है, जिससे उद्योग के भीतर कार्यबल की स्वीकार्यता बढ़ती है।
- **कौशल अंतराल को संबोधित करना:** इसका उद्देश्य उद्योग में आवश्यक कौशल के मानचित्रण पर जोर देकर कौशल अंतराल की पहचान करना और उसे पाटना है, अर्जित डिग्री और अर्जित व्यावहारिक कौशल के बीच असमानता को कम करना है।

- **दक्षताओं और ज्ञान का एकीकरण:** 21वीं सदी में प्रभावी ढंग से नेतृत्व करने के लिए व्यक्तियों को तैयार करने के लिए दक्षताओं, व्यावहारिक ज्ञान और व्यावहारिक प्रशिक्षण पर समान जोर दिया जाता है।

विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023



- विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023, अग्रणी वैश्विक स्वास्थ्य सम्मेलन और नेटवर्क, 15-17 अक्टूबर, 2023 को बर्लिन, जर्मनी में और ऑनलाइन आयोजित किया गया था।
- शिखर सम्मेलन का विषय था "वैश्विक स्वास्थ्य कार्रवाई के लिए एक निर्णायक वर्ष।"
- शिखर सम्मेलन ने सभी के लिए बेहतर स्वास्थ्य और कल्याण के लिए अभिनव समाधानों को प्रेरित करके एक स्वस्थ भविष्य के लिए एजेंडा निर्धारित करने के लिए दुनिया भर से राजनीति, विज्ञान, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज के हितधारकों को एक साथ लाया।
- शिखर सम्मेलन में कई विशेष कार्यक्रम भी शामिल थे, जिनमें वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा पर एक उच्च स्तरीय पैनल, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज पर एक मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन और स्वास्थ्य के भविष्य पर एक युवा मंच शामिल था।

केंद्रीय विषय:

- भविष्य में महामारी की रोकथाम, तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए COVID-19 से सीखना।
- सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लिए प्रतिबद्ध होना।
- लोगों और ग्रह के लिए स्थायी स्वास्थ्य।

- G7/G20 वैश्विक स्वास्थ्य समानता और सुरक्षा बढ़ाने के उपाय।
- वैश्विक स्वास्थ्य के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों की शक्ति का उपयोग करना।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन की 75वीं वर्षगांठ।

मुख्य परिणाम:

- वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा और महामारी तैयारियों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता।
- सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लिए एक नवीनीकृत प्रतिबद्धता।
- जलवायु संकट और स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव को संबोधित करने के लिए कार्रवाई का आह्वान।
- वैश्विक स्वास्थ्य के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों के महत्व की मान्यता।
- सभी के लिए एक स्वस्थ भविष्य बनाने के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता।

भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच रुपये घरेलू कार्ड योजना (डीसीएस) समझौता

- नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (एनआईपीएल) ने संयुक्त अरब अमीरात में घरेलू कार्ड योजना (डीसीएस) कार्यान्वयन के लिए अल एतिहाद पेमेंट्स (ईपी) के साथ एक रणनीतिक साझेदारी समझौता किया है। ईपी सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई (सीबीयूई) की एक अप्रत्यक्ष सहायक कंपनी है। समझौते के अनुसार, एनआईपीएल और ईपी यूएई की राष्ट्रीय घरेलू कार्ड योजना के निर्माण, कार्यान्वयन और संचालन के लिए मिलकर काम करेंगे।
- डीसीएस का लक्ष्य यूएई में ई-कॉमर्स और डिजिटल लेनदेन के विकास को सुविधाजनक बनाना, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, यूएई के डिजिटलीकरण एजेंडे का समर्थन करना, वैकल्पिक भुगतान विकल्पों को बढ़ाना, भुगतान की लागत को कम करना और वैश्विक स्तर पर यूएई की प्रतिस्पर्धात्मकता और स्थिति को बढ़ाना होगा। भुगतान के नेता, यह साझेदारी अन्य देशों को अपनी लागत-कुशल और सुरक्षित भुगतान प्रणाली स्थापित करने में सहायता करने के लिए अपने ज्ञान और विशेषज्ञता की पेशकश करने के एनआईपीएल के मिशन के साथ पूरी तरह से मेल खाती है।

डीसीएस समाधान संप्रभुता, बाजार में गति, नवाचार, डिजिटलीकरण और रणनीतिक स्वतंत्रता के सिद्धांतों पर आधारित है। एनआईपीएल द्वारा प्रदान किए गए डीसीएस समाधान में रुपये स्टैक और धोखाधड़ी निगरानी सेवाओं और विश्लेषण जैसी मूल्य वर्धित सेवाएं शामिल हैं। एनआईपीएल ईपी को उनकी घरेलू कार्ड योजना के लिए परिचालन नियम तैयार करने में भी सहायता करेगा।

- RuPay भारत में एक स्वदेशी, अत्यधिक सुरक्षित और व्यापक रूप से स्वीकृत कार्ड भुगतान नेटवर्क है। RuPay कार्ड में डेबिट, क्रेडिट और प्रीपेड प्रस्ताव हैं। आज की तारीख में 750 मिलियन से अधिक RuPay कार्ड प्रचलन में हैं। भारत में जारी किए गए कुल कार्डों में से 60% से अधिक RuPay कार्ड हैं, अब हर दूसरे भारतीय के पास RuPay कार्ड है। ये कार्ड सार्वजनिक क्षेत्र, निजी और छोटे बैंकों सहित संपूर्ण बैंकिंग स्पेक्ट्रम के माध्यम से जारी किए जाते हैं।
- भारत का विश्व-प्रसिद्ध डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) भुगतान क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बदलाव ला रहा है। डीपीआई ढांचे में डिजिटल पहचान, डिजिटल भुगतान और डिजिटल डेटा विनिमय परतें शामिल हैं - इन तीनों का संयोजन भारत में फिनटेक क्रांति के पीछे की ताकत है। सीधे शब्दों में कहें तो, भारत में, लगभग हर वयस्क के पास बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच है, खुद को दूर से प्रमाणित करने का एक तरीका (आधार के माध्यम से), और कुशल और किफायती मोबाइल कनेक्टिविटी के माध्यम से इंटरनेट तक पहुंच है।
- इन कारकों का संयोजन भारत को तेजी से सामने आने वाले यूनिकॉर्न के साथ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा फिनटेक पारिस्थितिकी तंत्र बनाता है। भारत में पिछले पांच वर्षों में डिजिटल लेनदेन में भाग लेने वाले ग्राहकों में 367% की तेजी से वृद्धि देखी गई है, जिसका सक्रिय ग्राहक आधार 340 मिलियन से अधिक है।

नीलवंडे बांध



- पीएम ने **महाराष्ट्र** के अहमदनगर जिले में नीलवंडे बांध का लोकार्पण किया।
- नीलवंडे बांध दो संबंधित **गुरुत्वाकर्षण बांधों** को संदर्भित करता है।
- दोनों बांध 250 मेगावाट पंप-भंडारण पनबिजली स्टेशन के लिए निचले और ऊपरी जलाशय का निर्माण करते हैं।
- ऊपरी नीलवंडे बांध गोदावरी नदी की सहायक नदी प्रवरा नदी पर है। निचला नीलवंडे बांध 86 शाही नाला नदी पर है।
- बांध का काम 1970 में शुरू हुआ था लेकिन इसमें काफी देरी हुई।
- इस बांध से अहमदनगर और नासिक के 182 गांवों के किसानों को लाभ होने की उम्मीद है।

- इससे भारत-जापान संबंध मजबूत होंगे।

उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना



भारत-जापान निधि

यह क्या है?

- भारत-जापान फंड भारत के राष्ट्रीय निवेश और बुनियादी ढांचा कोष (एनआईआईएफ) और जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन (जेबीआईसी) के बीच 600 मिलियन डॉलर का संयुक्त निवेश कोष है।
- यह फंड भारत में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश के लिए 2023 में लॉन्च किया गया था।
- यह फंड ऊर्जा, परिवहन, रसद, और जल और स्वच्छता सहित विभिन्न क्षेत्रों में निवेश को लक्षित कर रहा है। यह उन परियोजनाओं में निवेश करने में भी रुचि रखता है जो सतत विकास और जलवायु कार्रवाई का समर्थन करते हैं।
- भारत-जापान फंड भारत-जापान संबंधों के लिए एक महत्वपूर्ण विकास है और उम्मीद है कि यह भारत में बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
- भारत-जापान फंड जिन परियोजनाओं में निवेश कर सकता है वे हैं नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएँ, स्मार्ट शहर परियोजनाएँ, सड़क और राजमार्ग परियोजनाएँ, रेलवे परियोजनाएँ, बंदरगाह और हवाई अड्डा परियोजनाएँ, जल और स्वच्छता परियोजनाएँ आदि।

लाभ:

- यह भारत में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण का एक नया स्रोत प्रदान करेगा।
- इससे भारत में बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता और दक्षता में सुधार करने में मदद मिलेगी।
- इससे नौकरियाँ पैदा होंगी और भारत में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

- उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना एक अंतरराज्यीय प्रमुख सिंचाई परियोजना है जो भारत के झारखंड के लातेहार और गढ़वा जिलों और बिहार के औरंगाबाद और गया जिलों में स्थित है।
- परियोजना 1972 में शुरू हुई।
- बेतला नेशनल पार्क और पलामू टाइगर रिजर्व को डूबने से बचाने के लिए बिहार सरकार के वन विभाग द्वारा 1993 में इसे रोक दिया गया था।

उद्देश्य:

- झारखंड में पलामू और गढ़वा जिलों और बिहार में औरंगाबाद और गया जिलों के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई प्रदान करना। परियोजना का कुल कमांड क्षेत्र 1,02,272 हेक्टेयर है, जिसमें से लगभग 76% झारखंड में और 24% हेक्टेयर बिहार में है।
- उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना झारखंड और बिहार के सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए एक महत्वपूर्ण विकास है। यह परियोजना भूमि के एक बड़े क्षेत्र को सिंचाई प्रदान करेगी, जिससे कृषि उत्पादन बढ़ाने और किसानों की आजीविका में सुधार करने में मदद मिलेगी। यह परियोजना गरीबी को कम करने और क्षेत्र की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार करने में भी मदद करेगी।

अन्य लाभ:

- बाढ़ नियंत्रण
- जलविद्युत उत्पादन
- मत्स्य पालन विकास
- पर्यटन विकास

राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति (NCCM)

- यह प्राकृतिक आपदाओं और अन्य आपात स्थितियों की प्रतिक्रिया के समन्वय और प्रबंधन के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक उच्च स्तरीय समिति है।
- इसकी अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करते हैं और इसमें सभी संबंधित मंत्रालयों और एजेंसियों के साथ-साथ राज्य सरकारों के प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं।

जिम्मेदारियाँ:

- स्थिति की निगरानी करना और सहायता की आवश्यकता का आकलन करना
- प्रभावित क्षेत्रों में केंद्रीय संसाधनों की तैनाती
- राहत एवं बचाव कार्यों का समन्वय करना
- प्रभावित लोगों को आवश्यक सेवाओं का प्रावधान सुनिश्चित करना
- प्रभावित राज्यों और व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना
- भविष्य की आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए दीर्घकालिक उपायों की सिफारिश करना

भारत-यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद

- भारत-यूरोपीय व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद (टीटीसी) भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार और प्रौद्योगिकी पर बातचीत और सहयोग के लिए एक उच्च स्तरीय मंच है। टीटीसी को अप्रैल 2022 में लॉन्च किया गया था और इसकी पहली बैठक मई 2023 में हुई थी।
- व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद से भारत-यूरोपीय संघ संबंधों को मजबूत करने और दोनों पक्षों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है। टीटीसी जलवायु परिवर्तन और सुरक्षा जैसी आम चुनौतियों से निपटने में भी मदद करेगा।

केंद्रित मुद्दे:

- वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार
- डिजिटल व्यापार और प्रौद्योगिकी
- निवेश
- बौद्धिक संपदा अधिकार
- जलवायु परिवर्तन और सतत विकास
- सुरक्षा और बचाव

लाभ:

- भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार और निवेश में वृद्धि
- डिजिटल व्यापार और प्रौद्योगिकी पर सहयोग बढ़ाया
- जलवायु परिवर्तन और अन्य वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए संयुक्त प्रयास
- सुरक्षा और रक्षा सहयोग को मजबूत किया
- भारत और यूरोपीय संघ के बीच गहरी समझ और आपसी सम्मान

क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस)



- पीएम ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भारत का पहला क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) लॉन्च किया।
- प्रधानमंत्री ने आधिकारिक तौर पर दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर के प्राथमिकता वाले हिस्से को खोला।
- उन्होंने नमो भारत रैपिडएक्स ट्रेन के प्रस्थान का भी संकेत दिया, जो साहिबाबाद और दुहाई डिपो के बीच चलती है और भारत के क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) का उद्घाटन करती है।

- यह देश की पहली सेमी-हाई-स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा है।

दिल्ली-मेरठ आरआरटीएस की विशेषताएं:

- ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकेगी।
- एक ट्रेन अटेंडेंट भी है।
- प्रीमियम कोच विशाल, आलीशान है और इसमें झुकने वाली, गद्देदार कुर्सियाँ हैं जिनमें प्रत्येक सीट पर लैपटॉप और स्मार्टफोन के लिए चार्जिंग पोर्ट हैं।

जापान-भारत सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी

प्रसंग:

- केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जापान-भारत सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी पर सहयोग के एक ज्ञापन को मंजूरी दी गई।

विशिष्टताएँ:

- भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और जापानी अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय ने जुलाई 2023 में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
- उद्योगों और डिजिटल प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए सेमीकंडक्टर के महत्व को समझते हुए, सहयोग-ज्ञापन सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला में सुधार के लिए जापान और भारत के बीच सहयोग को गहरा करना चाहता है।
- इस पर हस्ताक्षर होने के बाद यह समझौता पांच साल तक प्रभावी रहेगा।
- यह सहयोग-ज्ञापन देश के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण उद्योग के लिए अनुकूल माहौल बनाने की सरकार की पहल का एक घटक है।
- मंत्रालय सूचना प्रौद्योगिकी के अत्याधुनिक और विकासशील क्षेत्रों में वैश्विक सहयोग पर जोर दे रहा है।

प्रवर्तन मामलों में सहयोग पर वैश्विक सम्मेलन (जीसीसीईएम)

यह क्या है?

- प्रवर्तन मामलों में सहयोग पर वैश्विक सम्मेलन (जीसीसीईएम) विश्व सीमा शुल्क संगठन (डब्ल्यूसीओ) के सहयोग से भारत के राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) द्वारा आयोजित एक सम्मेलन है।
- जीसीसीईएम दुनिया भर की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए एक मंच है जो एक साथ आते हैं और सीमा शुल्क और संबंधित कानूनों के प्रवर्तन में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा करते हैं।
- जीसीसीईएम में दुनिया भर के 40 से अधिक सीमा शुल्क प्रशासन और संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले 75 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में डब्ल्यूसीओ सचिवालय के वरिष्ठ प्रतिनिधि भी भाग ले रहे हैं।
- जीसीसीईएम कानून प्रवर्तन सहयोग के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण घटना है। उम्मीद है कि सम्मेलन अवैध व्यापार और अन्य अपराधों के खिलाफ लड़ाई में सीमा शुल्क प्रशासन और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए कई ठोस पहलों को जन्म देगा।

फोकस:

- नशीली दवाओं, हथियारों और अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं का अवैध व्यापार
- व्यापार-आधारित मनी लॉन्ड्रिंग
- तस्करी और जालसाजी
- कर चोरी और धोखाधड़ी
- साइबर क्राइम



UPSC CSE 2022 RESULT




Throughout the journey of UPSC CSE exam I have been consistently mentored by Amit Sir (The Core IAS). He has been the guiding light for me in all the stages: Prelims, Mains & Interview.

As opposed to conventional pedagogy and study methods, Sir has a unique way of that understanding of each exam is deeply helped me to be an outlier.

I convey my utter gratitude for mentoring me as an Officer today.

- Regards
Akansha Jain
AIR-702
UPSC CSE 2022

AKANSHA

AIR-702

योजना

प्रधान मंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना

- प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना 03 केंद्र प्रायोजित योजनाओं अर्थात् प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता और बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना की एक विलय योजना है और इसे कौशल विकास, आय सृजन योजनाओं और अन्य पहलों के माध्यम से अतिरिक्त रोजगार के अवसर पैदा करके अनुसूचित जाति समुदायों की गरीबी कम करने और अनुसूचित जाति बहुल गांवों में पर्याप्त बुनियादी ढांचे और अपेक्षित सेवाओं को सुनिश्चित करके सामाजिक-आर्थिक विकास संकेतकों में सुधार करने के उद्देश्य से 2021-22 से लागू किया गया है।

योजना के तीन घटक हैं:

1. अनुसूचित जाति बहुल गांवों का आदर्श ग्राम के रूप में विकास।
2. अनुसूचित जाति की सामाजिक-आर्थिक बेहतरी के लिए जिला/राज्य-स्तरीय परियोजनाओं के लिए सहायता अनुदान जिसमें आदर्श ग्राम घटक के तहत चयनित गांवों सहित अनुसूचित जाति बहुल गांवों में बुनियादी ढांचे का निर्माण, छात्रावास/आवासीय विद्यालयों का निर्माण, व्यापक आजीविका शामिल हो सकता है। परियोजनाएं जिनमें कौशल विकास, संबंधित बुनियादी ढांचे का विकास, आजीविका सृजन के लिए आवश्यक संपत्तियों के अधिग्रहण/निर्माण के लिए लाभार्थियों द्वारा लिए गए ऋण के लिए वित्तीय सहायता आदि जैसे घटक शामिल हो सकते हैं।
3. उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रावासों का निर्माण जो भारत सरकार के राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) के अनुसार शीर्ष क्रम में हैं और केंद्र/राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से वित्त पोषित हैं। इसी प्रकार, स्कूलों में छात्रावासों का निर्माण जो पूरी तरह या आंशिक रूप से केंद्र/राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा वित्त पोषित हैं और शिक्षा मंत्रालय द्वारा अनुशंसित हैं।

आदर्श ग्राम घटक [तत्कालीन प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना] के उद्देश्य-

- इस घटक का उद्देश्य अनुसूचित जाति बहुल गांवों का एकीकृत विकास सुनिश्चित करना है ताकि, अन्य बातों के साथ-साथ, पर्याप्त बुनियादी ढांचा,

सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए आवश्यक सभी आवश्यक बुनियादी ढांचा उपलब्ध हो।

- पहचाने गए सामाजिक-आर्थिक संकेतक, जिन्हें निगरानी योग्य संकेतक के रूप में जाना जाता है, में सुधार किया जाना है ताकि एससी और गैर-एससी आबादी के बीच असमानता समाप्त हो सके और संकेतकों का स्तर कम से कम राष्ट्रीय औसत तक बढ़ाया जा सके।
- अधिक विशेष रूप से, सभी बीपीएल एससी परिवारों को भोजन और आजीविका सुरक्षा मिलनी चाहिए, सभी एससी बच्चों को कम से कम माध्यमिक स्तर तक शिक्षा पूरी करनी चाहिए, मातृ और शिशु मृत्यु दर के सभी कारकों पर ध्यान दिया जाना चाहिए और विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं में कुपोषण की घटनाओं पर अंकुश लगाना चाहिए।

अनुसूचित जाति की सामाजिक-आर्थिक बेहतरी के लिए जिला/राज्य-स्तरीय परियोजनाओं के लिए अनुदान सहायता के बारे में [अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता की पूर्ववर्ती योजना]

इस योजना का लक्ष्य निम्नलिखित प्रकार की परियोजनाओं के लिए अनुदान के माध्यम से अनुसूचित जाति का सामाजिक-आर्थिक विकास करना है:

1. **व्यापक आजीविका परियोजनाएँ:** ऐसी परियोजनाएँ जो स्थायी आय उत्पन्न करने, या अनुसूचित जातियों के लिए सामाजिक उन्नति के लिए एक संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करती हैं, केवल तभी शुरू की जाएंगी। परियोजनाएँ अधिमानतः निम्नलिखित में से दो या अधिक का संयोजन होनी चाहिए:
 - i. **कौशल विकास:** एमएसडीई के मानदंडों के अनुसार कौशल पाठ्यक्रम। सरकार द्वारा संचालित कौशल विकास गतिविधियों के संचालन के लिए संबंधित सुविधाएँ और बुनियादी ढांचा। कौशल विकास संस्थानों को भी वित्त पोषित किया जा सकता है।
 - ii. **लाभार्थियों/परिवारों के लिए परिसंपत्तियों के निर्माण/अधिग्रहण हेतु अनुदान:** योजना के तहत कोई स्टैंडअलोन व्यक्तिगत संपत्ति वितरण नहीं होगा। हालाँकि, यदि परियोजना में लाभार्थियों/परिवारों के लिए आजीविका सृजन के लिए आवश्यक संपत्तियों के अधिग्रहण/निर्माण का प्रावधान है, तो ऐसे अधिग्रहण/संपत्तियों के निर्माण के लिए लाभार्थी द्वारा

लिए गए ऋण के लिए वित्तीय सहायता 50,000 रुपये या संपत्ति लागत का 50%, जो भी कम हो, प्रति लाभार्थी/घर तक होगी।

iii. **बुनियादी ढांचे का विकास:** परियोजना से संबंधित बुनियादी ढांचे और छात्रावासों और आवासीय विद्यालयों का विकास।

2. **अन्य बुनियादी ढाँचा-** अनुसूचित जाति बहुल गाँवों में विभिन्न अन्य बुनियादी ढाँचा विकास परियोजनाएँ।

विशेष प्रावधान:

- कुल अनुदान का 15% तक विशेष रूप से अनुसूचित जाति महिलाओं के लिए व्यवहार्य आय पैदा करने वाली आर्थिक विकास योजनाओं/कार्यक्रम पर।
- बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कुल अनुदान का 30% तक उपयोग किया जाता है।
- कौशल विकास के लिए कुल धनराशि का कम से कम 10%।
- उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और विपणन में लगी अनुसूचित जाति महिला सहकारी समितियों को बढ़ावा देना।

सघन मिशन इंद्रधनुष (आईएमआई) 5.0



- यह एक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान है।
- भारत में बच्चों और गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण अभियान।
- अभियान की सफलता माता-पिता, देखभाल करने वालों और स्वास्थ्य कर्मियों सहित सभी हितधारकों की भागीदारी पर निर्भर करेगी।

द्वारा कार्यान्वित: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राज्य सरकारों और अन्य भागीदारों के सहयोग से।

उद्देश्य:

- दो वर्ष से कम उम्र के बच्चों और गर्भवती महिलाओं तक पहुंचने के लिए जो अपने नियमित टीकाकरण से चूक गए हैं। आईएमआई 5.0 तीन चरणों में आयोजित किया जा रहा है, प्रत्येक चरण चार सप्ताह तक चलेगा।
- 2023 तक दोनों संक्रमणों को खत्म करने के लक्ष्य के साथ, खसरा और रूबेला टीकाकरण के कवरेज में सुधार पर ध्यान केंद्रित करना।
- अभियान अन्य नियमित टीके, जैसे पोलियो वैक्सीन, पेंटावैलेंट वैक्सीन और बीसीजी वैक्सीन प्रदान कर रहा है।

रणनीतियाँ:

- घर-घर जाकर टीकाकरण
- मोबाइल टीकाकरण टीमों
- स्थिर टीकाकरण केंद्र
- समुदायों में आउटरीच गतिविधियाँ

लाभ:

- बाल मृत्यु दर और रुग्णता में कमी
- खसरा और रूबेला के लिए बेहतर टीकाकरण कवरेज
- 2023 तक खसरा और रूबेला का उन्मूलन
- अन्य रोकथाम योग्य बीमारियों से सुरक्षा
- टीकाकरण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ी

राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना (एनएमएमएसएस)

- केंद्रीय क्षेत्र योजना
- इसमें राज्य सरकार के अधीन स्कूलों के अलावा सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकाय स्कूल भी शामिल हैं।
- यह योजना राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर उपलब्ध है।

उद्देश्य:

- आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मेधावी छात्रों को माध्यमिक स्तर पर अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए स्कूल छोड़ने की दर को कम करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करना।

पात्रता मापदंड:

- वे छात्र जिनके माता-पिता की सभी स्रोतों से आय प्रति वर्ष ₹ 3,50,000 से अधिक नहीं है, वे छात्रवृत्ति का लाभ उठाने के पात्र हैं।

- छात्रवृत्ति के पुरस्कार के लिए चयन परीक्षा में उपस्थित होने के लिए छात्रों के पास सातवीं कक्षा की परीक्षा में न्यूनतम 55% अंक या समकक्ष ग्रेड होना चाहिए (एससी/एसटी छात्रों के लिए 5% की छूट)।

डिजिटल इंडिया

- डिजिटल इंडिया भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है।

Digital India Power To Empower

डिजिटल इंडिया के तीन मुख्य घटक हैं:

- **एक उपयोगिता के रूप में बुनियादी ढाँचा:** इस घटक का लक्ष्य एक मजबूत और सर्वव्यापी डिजिटल बुनियादी ढाँचा बनाना है, जिसमें ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, सार्वजनिक वाई-फाई हॉटस्पॉट और मोबाइल कनेक्टिविटी शामिल है।



- **मांग पर शासन और सेवाएँ:** इस घटक का उद्देश्य नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से सरकारी सेवाएँ प्रदान करना है। इसमें ई-गवर्नेंस, ई-स्वास्थ्य और ई-शिक्षा जैसी पहल शामिल हैं।



नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण: इस घटक का उद्देश्य नागरिकों को डिजिटल साक्षरता और कौशल से सशक्त बनाना है। इसमें डिजिटल साक्षरता मिशन और स्किल इंडिया जैसी पहल शामिल हैं।



डिजिटल इंडिया का भारत की अर्थव्यवस्था और समाज पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। इसने सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि को बढ़ावा देने, नौकरियाँ पैदा करने और सरकारी सेवाओं की डिलीवरी में सुधार करने में मदद की है। डिजिटल इंडिया ने व्यवसायों के संचालन और नागरिकों के लिए सूचना और सेवाओं तक पहुंच को आसान बना दिया है।

प्रमुख डिजिटल इंडिया पहल:

- **भारतनेट:** भारतनेट एक ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी परियोजना है जिसका लक्ष्य भारत की सभी 600,000 ग्राम पंचायतों को हाई-स्पीड इंटरनेट से जोड़ना है।



- **डिजिटल लॉकर:** डिजिटल लॉकर एक सुरक्षित ऑनलाइन भंडार है जहां नागरिक अपने डिजिटल दस्तावेज, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस संग्रहीत और साझा कर सकते हैं।



- **ई-साइन:** ई-साइन एक डिजिटल हस्ताक्षर सेवा है जो नागरिकों को अपने आधार कार्ड का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने की अनुमति देती है।



- **एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI):** UPI एक वास्तविक समय भुगतान प्रणाली है जो उपयोगकर्ताओं को अपने स्मार्टफोन का उपयोग करके बैंक खातों के बीच धन हस्तांतरित करने की अनुमति देती है।



- **MyGov:** MyGov नागरिकों के लिए सरकार के साथ जुड़ने और अपने विचार और सुझाव साझा करने का एक मंच है।

THE CORE IAS

ए-हेल्प' कार्यक्रम



- **आधार:** आधार भारत के प्रत्येक निवासी को सौंपी गई एक विशिष्ट पहचान संख्या है। आधार का उपयोग सरकारी सेवाओं, बैंकिंग और दूरसंचार सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है।

- **ए-हेल्प (पशुधन उत्पादन के स्वास्थ्य और विस्तार के लिए मान्यता प्राप्त एजेंट) कार्यक्रम** केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक पहल है।

- 2023 में लॉन्च किया गया।
- **उद्देश्य:** महिलाओं को सशक्त बनाना और ग्रामीण भारत में पशुधन स्वास्थ्य और उत्पादकता में सुधार करना। ए-हेल्प कार्यक्रम के तहत, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की महिला सदस्यों को स्वास्थ्य और पशुधन उत्पादन के विस्तार के लिए मान्यता प्राप्त एजेंटों के रूप में प्रशिक्षित किया जाता है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन
- सरकारी पशु चिकित्सा सेवाओं पर बोझ कम हुआ

‘हार्टलैंड त्रिपुरा’ परियोजना

सेवाएँ:

- पशुओं को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करना
- पशुधन रोगों की रोकथाम और नियंत्रण में सहायता करना
- कृत्रिम गर्भाधान और अन्य प्रजनन प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना
- पशुधन प्रबंधन प्रथाओं पर जानकारी प्रदान करना
- किसानों को सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों से जोड़ना

लाभ:

- पशुधन स्वास्थ्य और उत्पादकता में सुधार
- पशुपालकों की आय में वृद्धि
- महिलाओं का सशक्तिकरण

- **परियोजना का लक्ष्य त्रिपुरा के इंजीनियरिंग और गैर-इंजीनियरिंग क्षेत्रों में स्नातक छात्रों को नए करियर और व्यक्तिगत विकास की संभावनाएं प्रदान करना है।** यह परियोजना डेलॉइट इंडिया और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (NIELIT), अगरतला के सहयोग से शुरू की गई थी और इसे संघीय सरकार और त्रिपुरा राज्य दोनों द्वारा समर्थित किया गया था।
- NIELIT-अगरतला के माध्यम से, परियोजना राज्य को कौशल विकास प्रमाणन पाठ्यक्रमों का एक विशिष्ट सेट प्रदान करेगी। इसके अतिरिक्त, यह चयनित पेशेवरों को इंटर्न करने का मौका प्रदान करेगा, अंततः प्रमाणन और इंटर्नशिप आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद आकर्षक करियर अवसरों के लिए द्वार खोलेगा।
- सॉफ्ट स्किल्स, आंतरिक ऑडिट, एनालिटिक्स और साइबर सुरक्षा सहित विभिन्न प्रकार की आधुनिक तकनीकी और व्यावसायिक विकास क्षमताओं को परियोजना द्वारा प्रदान किए गए प्रमाणन कार्यक्रमों द्वारा कवर किया जाएगा।



रिपोर्ट / सूचकांक

भारत में सड़क दुर्घटनाएँ-2022

- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 'भारत में सड़क दुर्घटनाएँ-2022' पर वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। यह रिपोर्ट एशिया प्रशांत सड़क दुर्घटना डेटा (APRAD) आधारित परियोजना के तहत एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग (UNESCAP) द्वारा प्रदान किए गए मानकीकृत प्रारूपों में कैलेंडर वर्ष के आधार पर राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के पुलिस विभागों से प्राप्त डेटा/जानकारी पर आधारित है।
- रिपोर्ट के अनुसार, कैलेंडर वर्ष 2022 के दौरान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) द्वारा कुल 4,61,312 सड़क दुर्घटनाएँ दर्ज की गईं, जिनमें 1,68,491 लोगों की जान चली गई और 4,43,366 लोग घायल हो गए। पिछले वर्ष की तुलना में दुर्घटनाओं में 11.9%, मृत्यु में 9.4% और चोटों में 15.3% की वृद्धि हुई है।
- रिपोर्ट इन दुर्घटनाओं में योगदान देने वाले कारकों को संबोधित करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाने की तात्कालिकता पर जोर देती है, जिसमें तेज गति, लापरवाही से गाड़ी चलाना, नशे में गाड़ी चलाना और यातायात नियमों का अनुपालन न करना शामिल है। यह महत्वपूर्ण है कि हम प्रवर्तन तंत्र को मजबूत करें, ड्राइवर शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ाएं और सड़कों और वाहनों की स्थिति में सुधार करने में निवेश करें।
- मंत्रालय सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए मजबूत उपाय लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्रालय सड़क उपयोगकर्ता व्यवहार, सड़क बुनियादी ढांचे, वाहन मानकों, यातायात नियमों को लागू करने और दुर्घटना की रोकथाम में प्रौद्योगिकी की भूमिका जैसे विभिन्न पहलुओं पर भी काम कर रहा है। चूँकि सड़क दुर्घटनाएँ प्रकृति में बहु-कारणीय होती हैं, इसलिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों दोनों की सभी एजेंसियों के ठोस प्रयासों के माध्यम से समस्याओं को

कम करने के लिए बहु-आयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। मंत्रालय ने विभिन्न अन्य संबंधित संगठनों के साथ-साथ हितधारकों के साथ मिलकर शिक्षा, इंजीनियरिंग (सड़क और वाहन दोनों), प्रवर्तन और आपातकालीन देखभाल सहित सभी 4ई पर ध्यान केंद्रित करते हुए सड़क सुरक्षा के मुद्दे को संबोधित करने के लिए एक बहु-आयामी रणनीति तैयार की है।

- इसके अलावा, मंत्रालय आधुनिक परिवहन प्रणालियों के कार्यान्वयन, सड़क सुरक्षा ऑडिट और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं से सीखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जैसी पहलों में सक्रिय रूप से शामिल है। सड़क दुर्घटनाओं से निपटने के लिए वास्तविक समय डेटा विश्लेषण और स्वचालित वाहन निरीक्षण केंद्रों के लिए इलेक्ट्रॉनिक विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट (ई-डीएआर) जैसी पहल भी चल रही हैं।
- "भारत में सड़क दुर्घटनाएँ-2022" प्रकाशन सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं और हितधारकों के लिए एक मूल्यवान संसाधन के रूप में कार्य करता है। यह सड़क दुर्घटनाओं के विभिन्न पहलुओं, उनके कारणों, स्थानों और सड़क उपयोगकर्ताओं की विभिन्न श्रेणियों पर उनके प्रभाव सहित गहराई से जानकारी प्रदान करता है। रिपोर्ट उभरते रुझानों, चुनौतियों और मंत्रालय की सड़क सुरक्षा पहलों पर भी प्रकाश डालती है।



OUR CLASSROOM RESULTS NOT OF INTERVIEW



JATIN JAIN
(Rank-91) UPSC CSE-2022



SHRUTI
(Rank 165) UPSC CSE-2022



DAMINI DIWAKAR
(Rank 435) UPSC CSE-2022



AKANSHA
(Rank 702) CSE-2022



UPSC 2021-RANK 152
NEHA JAIN



ABHI JAIN
(Rank 282) 2021



VASU JAIN
(Rank 67) 2020



AKASH SHRISHRIMAL
(Rank 94) 2020



DARSHAN
(Rank 138) 2020



SHREYANSH SURANA
(Rank 269) 2020



ARPIT JAIN
(Rank 279) 2020



SANDHI JAIN
(Rank 329) 2020



RAJAT KUMAR PAL
(Rank 394)



SANGEETA RAGHAV
(Rank 21-2018 UPPSC)



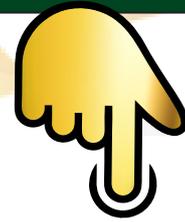
PANKHURI JAIN
2018 UPPSC



ABHISHEK KUMAR
(Rank 38) 2018 UPPSC



Scan here for Testimonial



103, B-5/6 II Floor, Himalika Commercial
Complex Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 09

53/18, Old Rajinder Nagar,
New Delhi, 110060

011-41008973, 8800141518, 9873833547